


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम
जितेन्द्र कुमार सागरसम
किस्म मुकदमा मु. नं० 12 वर्ष 2018
225

दिनांक	आज्ञा पत्र
1.2.2018	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने छ भूमि ख०नं० 94 ख०ख०, 94/328, 95, 96, 97, 98, 99 कुल कित्ता-7 रकबा 5.22 हेक्टर ग्राम कदमा का बास में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा है । रैस्पोंडेंट्स उक्त आराजी को बिना बटवारा किये ही बैचान करने पर आमादा है । इस निवेदन को अदालत मातहत ने नजर अन्दाज कर मेरा छ सर्वे स्थगन प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया कि अप्रार्थीगण सह खातेदार कार्तकार है इस कारण उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अदालत मातहत ने मेरा प्रार्थना पत्र केवल दावा विभाजन का मानकर खारिज कर दिया । जबकि मेरा प्रार्थना पत्र उक्त आराजी को बैचान अन्तर नहीं करे राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति का था किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यो पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये रैस्पोंडेंट को पाबन्द किया जावे । बहस के समर्थन में आरआरटी 2016१२१ पेज 1205 पेरा की जिसमें निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपील ही होगी रिविजन नहीं होगा । अतः मेरा प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जावे ।</p>



बहस बगौर समाप्त की गई । अदालत मातहत क
निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में
विवादित आराजी को संयुक्त खातेदारी की मानकर
प्रार्थना पत्र को खारिज किया है । किन्तु विवादित
आराजी के अपीलान्ट भी सहखातेदार है ऐसी स्थिति

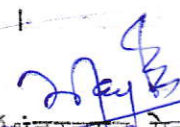

कृ-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पटेल राजेश्वर अपील अधिकारी
साकार

10/10/2014

में विवादित आराजी का अन्तरण अथवा बैयान हो जाता है प्रकरण में पक्षकारों के मध्य ओर अधिक पैचिदगीया बंदने की ही अधिक सम्भावनाए रहती है इस कारण हम अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान कार्यकारी अधिनियम का 2 माह में दोनों पक्षों को सुनकर विधि संगत निर्णय प्रारित करें तथा तब तक उभयपक्षों को हम स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना भी उचित मानते हैं कि वह विवादित आराजी का रहन बैय एवं किती प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी धोद का निर्णय दिनांक 27-12-2017 खारिज किया जाता है प्रकरण अदालत मातहत का इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनकर उच्छे उनके यहां विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा-212 का दो माह में निर्णय करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी का रहन बैय एवं किती प्रकार से अन्तरण नहीं करें । पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशगी पर उपस्थित होंगे ।

निर्णय सुनाया गया ।


11/2/18
अधीनस्थान मेडर डा
अधीनस्थान अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्रार्थिकारी
सीकर